अखिल भारतीय कामगार महिला
समन्वय समिति (सी आइ टी यू)

पत्रिका

जुलाई 1999

(केवल सदस्यों के लिए)

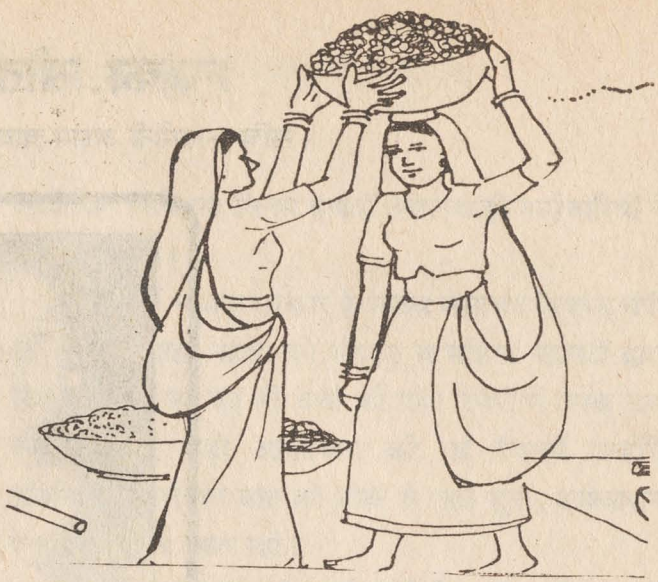

प्रिय पाठक

आपके पास कामकाजी महिलाओं की हिन्दी पत्रिका का पहला अंक पहुंचाते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। हम पिछले 19 वर्षों से द्विमासिक अंग्रेजी पत्रिका 'द वाइस ऑफ वर्किंग वूमन' प्रकाशित कर रहे हैं। साथ ही हम कुछ वर्षों तक हिन्दी पत्रिका 'कामकाजी महिला' प्रकाशित करते रहे; किन्तु आर्थिक कारणों से इसे बंद करना पड़ा। लोगों के द्वारा भेजे अनेक सुझावों व हिन्दी भाषी प्रदेशों की कामकाजी महिलाओं के संघर्षों व समस्याओं के आदान-प्रदान के लिए इस पत्रिका की आवश्यकता महसूस की गई। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 'सीटू' ने इस पत्रिका के प्रकाशन का निर्णय लिया। इसकी कीमत मात्र एक रुपया निर्धारित की गई है, ताकि इसे अधिकाधिक संख्या में कामकाजी महिलाओं तक पहुंचाया जा सके। हम आशा करते हैं कि आपको यह पत्रिका अवश्य पसंद आएगी व आप इस पत्रिका को अपने साथियों तक पहुँचाने में मदद करेंगे।

कृपया आप हमें अपने सुझाव, अनुभव, काम के स्थान की समस्या, लेख, छोटी कहानियाँ, कविताएँ आदि भेजें ताकि इन्हें पत्रिका में प्रकाशित किया जा सके।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप पत्रिका के लिए एक 'शीर्षक' (नाम) भेजें। जिस व्यक्ति का 'शीर्षक' स्वीकार किया जाएगा। उसे भेजा जाएगा:

* पत्रिका के दस अंक।
* एक सुन्दर रंगीन पोस्टर।
* 'वाइस आफ वर्किंग वूमन' की एक वर्ष तक' पत्रिका।

हम आशा करते हैं कि आप हमें अवश्य लिखेंगे।

अभिनंदन सहित!

संपादक

पता:

सीटू केन्द्रीय कार्यालय,
15 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली - 110001
दूरभाष: (011) 3714071, 3723825
फैक्स: 011-3355856,

श्रद्धांजलि

कारगिल में दुश्मनों से लड़ते शहीद हुए वीर जवानो को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के सदस्यों के साथ संवेदना प्रकट करते हैं। हम कामगार महिलाओं से अपील करते हैं कि वे जवानों के लिए सहायता दें। यह सहायता राष्ट्रीय सुरक्षा कोष या मुख्यमंत्री सुरक्षा कोष में जमा की जा सकती है।

का. सीता मराण्डी

(सचिव-नामोनी असम चाय मजदूर संघ, मोरनोई यूनिट)

प्रबंधकों और इंटक के गुंडों द्वारा कत्ल किया गया

16 मई, 1999 को चाय बागान मालिकों और उनके साथ षड्यन्त्र में शामिल 'इंटक' के लोगों के द्वारा भाड़े पर लाये गये हत्यारों ने 'सीटू' से संबंधित नामोनी असम मजदूर संघ की मोरनोई इकाई की महासचिव और सीटू राज्य कमेटी की सदस्या सीता मराण्डी समेत दो और कामगार महिलाओं की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी।

पिछले कई वर्षों से असम में मोरनोई चाय बागान के मालिक अपने शोषण को बरकरार रखने रखने और उसे बढ़ाने के क्रम में तथा सीटू के साथ मजदूरों के जुड़ाव को कम करने के लिए दमन और धमकियों का बराबर प्रयोग करते रहे हैं।

मजदूरों और नेताओं को न केवल सस्पेंड और बर्खास्त कर दिया जाता बल्कि उन पर बाकायदा हमले करवाये जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में ही 1996 में यूनियन की एक अग्रणी नेता सागरिका सोरेन की हत्या कर दी गयी थी। जनवरी 1999 में एक और बर्खास्त मजदूर अनाबृता बारला की हत्या कर दी गयी। स्वयं सीता मराण्डी को 1998 में बर्खास्त कर दिया गया। मगर इस सबके बावजूद भी जब साहस और लगन की प्रतीक बन गई सीता मराण्डी की आवाज को नहीं दबाया जा सका और वे निचले असम में खासतौर पर कोकराझार जिले में सीटू के झंडे को ऊँचा उठाती रहीं तो चाय बागान के मालिकों ने इंटक और स्थानीय प्रशासन से मिलकर अंततः उनकी हत्या कर दी।

अखिल भारतीय कामगार महिलाओं की कोआर्डिनेशन कमेटी इस निर्मम हत्याकांड की कड़ी भर्त्सना करती है। कमेटी उनके परिवार के प्रति असम राज्य कमेटी के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती है और यह शपथ लेती है कि उनके द्वारा किये जा रहे कार्य को आगे बढ़ाया जायेगा।

आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स की आल इंडिया फेडरेशन भी इस हत्याकांड की कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है। फेडरेशन ने एकजुटता प्रदर्शित करते हुए संघर्ष फंड में पांच हजार रुपये का योगदान किया है।

कोआर्डिनेशन कमेटी और आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स फेडरेशन सभी शुभ चिंतकों और हिमायतियों एकजुटता का इजहार करने और संघर्ष फंड में योगदान देने की अपील करती हैं। इस वाबत सहयोग डिमांड ड्राफ्ट के जरिये ''सीटू असम राज्य कमेटी'' गुवाहाटी पर देय के नाम निम्न पते पर भेजा जा सकता है:

महासचिव
सीटू, असम राज्य कमेटी
आनंद राम बरूआ रोड
श्रीमन्त प्रेस के पास
गुवाहाटी, असम- 781001

संगठन बढ़ाने का आह्वान

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स फेडरेशन की वर्किंग कमेटी की बैठक 9 मई '99 को दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता फेडरेशन की अखिल भारतीय अध्यक्ष नीलिमा मैत्रा ने की। बैठक में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, पांडिचेरी व आन्ध्र-प्रदेश के प्रतिनिधियों ने हिस्सेदारी ली। केरल में राज्य सम्मेलन की वजह से कोई प्रतिनिधि बैठक में नहीं आ सका। सभा की उपाध्यक्ष कॉमरेड अहिल्या रांगणेकर दिल्ली में रहते हुए बिमारी की वजह से बैठक में हिस्सा नहीं ले सकी। कुछ अन्य कारणों की मजबूरी के चलते कर्नाटक व गुजरात के साथी भी बैठक में नहीं आ पाये।

फेडरेशन की अखिल भारतीय महासचिव डा. के. हेमलता ने में पिछली मिटिंग से अब तक की गतिविधियों की लिखित रिपोर्ट बैठक में पेश की। 11 दिसम्बर की अखिल भारतीय आम हड़ताल व 2 फरवरी '99 के विरोध दिवस के अलावा, रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया कि आंगनवाड़ी मजदूरों की मांगों पर 18 फरवरी को हुए संघर्षों के कार्यक्रम काफी सफल रहे। इस कार्यक्रम के तहत् केरल, आन्ध्र प्रदेश, पांन्डिचेरी, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा असम, बिहार, मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों में जिला स्तरीय धरना, पिकेटिंग, रास्ता रोको, रेली व अन्य जन-लामबंदी के कार्यक्रम आयोजित किये गए जिनमें हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने हिस्सेदारी ली।

रिपोर्ट में भाजपा सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री श्री मुरली मनोहर जोशी को संगठन व महिला सांसदों द्वारा दिए गये मांग पत्र की भी चर्चा की गई। रिपोर्ट में उनके उस व्यवहार की कड़ी आलोचना की गई जिसमें उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल की बात को ठीक से नहीं सुना, आश्वासन देना तो दूर की बात रही।

रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करने के बाद सभी सदस्यों ने मिलकर भविष्य में संघर्षों को तेज करने व संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित फैसले लिये गये।

1. आंगनवाड़ी मजदूरों की मांगों को मनवाने के लिए जून-जुलाई '99 के महीने में राज्य स्तरीय संघर्ष किया जायेगा जिससे की राज्यों सरकारों को मांगें मानने पर मजबूर किया जा सके।

2. संगठन की सदस्यता जो कि वर्ष 98, के अन्त में 1 लाख थी, को बढ़ा कर 1999 में 1 लाख 50 हजार करने का फैसला लिया गया।

3. जुलाई माह में हिन्दी भाषी राज्यों के कार्यकर्ताओं के लिए 3 दिन के शिक्षण शिविर का आयोजन किया जायेगा।

हिन्दी राज्यों के लिए केन्द्रीय स्कूल

अखिल भारीय आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स यूनियन, हिन्दी भाषी राज्यों के यूनियन कार्यकर्ताओं के लिए तीन दिन के केन्द्रीय स्कूल का 10,11,12 जुलाई 1999 को 14, अशोक रोड, नई दिल्ली में आयोजित कर रहा है। इस स्कूल में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात महाराष्ट्र और दिल्ली से कुल पचास कार्यकर्ता भाग लेंगे। विभिन्न विषयों पर सी आई टी यू के नेता क्लास लेंगे। यह स्कूल हिन्दी भाषी क्षेत्रों में संगठन को मजबूत बनाने और आगे बढ़ाने का कार्यक्रम बनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

सीटू जनरल काउंसिल द्वारा कामकाजी महिलाओं की कोआर्डिनेशन कमेटी के काम की समीक्षा

- पिछले जून महीने में अखिल भारतीय कामकाजी महिलाओं की कोआर्डिनेशन कमेटी (सीटू) ने अपनी स्थापना के 20 वर्ष पूरे कर लिये। सीटू सचिव मंडल ने कामकाजी महिलाओं के बीच काम के इन दो दशकों के अनुभवों की समीक्षा करने का फैसला लेने के साथ ही सीटू में कामकाजी महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने और उसमें सुधार करने के लिए जरूरी कदम उठाने के बारे में भी चर्चा की। इस बारे में सीटू सचिवमंडल द्वारा तैयार किये गये 'नोट' पर सीटू की 27 से 29 मई 99 को गाजियाबाद में हुई जनरल काउंसिल की बैठक में चर्चा की गई।

- 'नोट' में यह स्पष्ट किया गया था कि कामकाजी महिलाओं की कोआर्डिनेशन कमेटी ने कामगार महिलाओं से जुड़े खास मुद्दों को 'सीटू' और उसके दायरे के बाहर भी सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। 'सीटू' की कुछ राज्य कमेटियाँ और संबंधित यूनियनें भी चर्चाओं, सम्मेलनों, और उप-कमेटियों के गठन के द्वारा कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान दे रही हैं।

- पिछले कुछ वर्षों से सीटू के अखिल भारतीय केन्द्र और, बहुत सारी राज्य कमेटियों ने तो यह जरूरी कर दिया है कि 'सीटू' के सम्मेलनों में प्रतिनिधियों का कम से कम 10 प्रतिशत महिलाओं का होगा।

- राष्ट्रीय स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हैल्पर्स को संगठित करने के फैसले से आंगनवाड़ी कर्मचारियों के आंदोलन को बल मिला है।

- 'कामगार महिलाओं की आवाज' नामक द्विमासिक पत्रिका अंग्रेजी में पिछले 19 वर्षों से बराबर प्रकाशित की जा रही है।

- सचिवमंडल द्वारा तैयार 'नोट' में कमियों की तरफ भी इशारा किया गया जैसे 'सीटू' की सदस्यता में महिलाओं की कम सदस्यता (13 प्रतिशत), महिला कार्यकर्ताओं को बैठकों में जाने के लिए वित्तीय मदद की कमी, महिला नेतृत्व को उभारने में हिचकिचाहट, बातचीत के लिए उन्हें साथ न ले जाना और कोआर्डिनेशन कमेटी की अनियमित या ठप्पप्राय फंक्शनिंग आदि।

- विभिन्न राज्यों लगभग 25 साथियों ने चर्चा में हिस्सा लिया और 'नोट' में दर्ज निष्कर्षों को सही ठहराया। जनरल काउंसिल ने सर्वसम्मति से, लागू करने के कार्यभार संबंधी निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किये-

1. कामगार महिलाओं के बीच कार्य करने के बारे में सीटू की सभी राज्य कमेटियाँ चर्चा कर प्राथमिकताओं की पहचान करते हुए एक समयबद्ध योजना तैयार करें। राज्य कमेटी के एक पदाधिकारी को इस बाबत स्वतंत्र जिम्मेदारी सौंपी जाये।
2. राज्य स्तर पर कोआर्डिनेशन कमेटियों का गठन किया जाना चाहिये और उनके काम को सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिये।
3. जिन कारखानों में बड़ी तादाद में महिला मजदूर काम करती हैं उनमें कारखाने के स्तर पर सब-कमेटियों का गठन किया जाये।
4. कामगार महिलाओं के लिए अलग से ट्रेड यूनियन कक्षायें आयोजित की जायें।
5. जहाँ-जहाँ पर संभव हो इस क्षेत्र में पूर्ण कालिक कार्यकर्ताओं को दिया जाये।

भारत में प्रतिदिन

* तीन दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है।
* दो दलित महिलाओं व पुरुष की हत्या होती है।
* दो दलित मकानों में आग लगाई जाती है।
* 48 दलित महिलाओं तथा पुरुषों पर हमला होता है।

हिमाचल प्रदेश: आंगनवाड़ी यूनियन मीटिंग

देवकी शर्मा

हिमाचल प्रदेश राज्य आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स यूनियन की राज्य स्तरीय बैठक 13 जून 99 को शिमला में हुई। राज्य के 15 खंडो से 30 सदस्यों ने बैठक में भागेदारी की। बैठक में फेडरेशन की अखिल भारतीय महासचिव साथी के. हेमलता के अलावा सीटू राज्य महासचिव कश्मीर सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। बैठक में किन्नौर जिले के तीन खंड के साथी भी लम्बी यात्रा करके पहुंचे। यह इलाका चीन की सीमा के साथ मिलता है।

साथी अवतार कौर व चन्द्र नेगी संगठन की अध्यक्षा तथा उपाध्यक्षा ने संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता की। राज्य महासचिव साथी देवकी शर्मा ने पिछली बैठक से इस बैठक के बीच की गतिविधियों की रपट पेश की। बैठक में सुपरवाईजर के पदों में आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आरक्षण की लंबित मांग पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इसके अलावा अतिरिक्त कार्य व प्रसूति अवकाश के मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा हुई तथा यह तय पाया गया कि उपरोक्त मांगों को हासिल करने के लिये संघर्ष को तेज किया जाये। बैठक में जुलाई में एक महीने के अभियान के अन्तर्गत परचे बांटना तथा सर्कल व प्रोजेक्ट कमेटियों की बैठकें करने की योजना बनाई गई। इस अभियान की समाप्ति 7 अगस्त को राज्य स्तरीय हड़ताल व जिला केन्द्रों पर जन रैली के जरिये होगी।

बैठक में यह भी फैसला किया गया कि राज्य केन्द्र जो मंडी से कार्य करता है को नियमित रूप से संगठन की गतिविधियों व फैसलों को अमल में लाने के लिये तालमेल बनाना होगा। यह कसरत सर्कल से लेकर प्रोजेक्ट कमेटी तक होनी चाहिए। दिल्ली में होने वाली हिन्दी भाषी राज्यों के शिक्षण शिविर के लिए प्रतिनिधियों के नाम भी तय किये गये तथा अगस्त के बाद तीन दिवसीय राज्य स्तरीय शिक्षण शिविर के आयोजन का फैसला भी लिया गया।

आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी यूनियन का तीसरा राज्य सम्मेलन

आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स यूनियन का तीसरा राज्य सम्मेलन 11 से 13 अप्रैल 99 को महबूब नगर जिले के शादनगर में संपन्न हुआ। राज्य के 22 जिलों से आयीं करीब 170 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। अखिल भारतीय फैडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स की अध्यक्षा नीलिमा मैत्र भी सम्मेलन में उपस्थित थीं।

सम्मेलन की शुरूआत से पहले 11 अप्रैल की शाम को एक प्रभावशाली जुलूस निक़ाला गया जिसमें हजारों आंगनवाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स ने हिस्सा लिया। शादनगर में इससे पहले 'महिलाओं का इतना बड़ा जुलूस कभी नहीं निकला था। जुलूस के बाद आयोजित की गई रैली को फेडरेशन की अध्यक्षा नीलिमा मैत्र, महासचिव हेमलता के अलावा सीटू की आंध्र प्रदेश राज्य कमेटी के अध्यक्ष एम ए गफूर और आंगनवाड़ी यूनियन की जिला सचिव विजया ने संबोधित किया।

तत्कालीन महासचवि के. हेमलता ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में पिछले सम्मेलन के बाद की अवधि के अनुभवों की समीक्षा करते हुए संगठन को संतुलित ढंग से सुदृढ बनाने और संघर्ष को कर्मचारियों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि यूनियन की संतुलित गतिविधियों के फलस्वरूप उसकी सदस्य संख्या लगभग 6,500 से बढ़कर 1998 में 24000 हो चुकी थी। रिपोर्ट में संघर्ष को और तेज करने का आह्वान किया गया ताकि राज्य सरकार अपने वादे पूरे करने के लिए विवश किया जा सके। रिपोर्ट पर बहस में 40 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बाद में नये पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। कामरेड ललिताम्मा तथा रोजा अध्यक्ष एवं महासचिव चुनी गईं।

केरल राज्य सम्मेलन

– पी. पद्मिनी

केरल राज्य आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स एसोसिएशन का चौथा सम्मेलन 14-15 मई 99 पलक्कड़ में संपन्न हुआ। राज्य के 14 जिलों से करीब 500 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। अखिल भारतीय फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स की महासचिव के. हेमलता और सचिव ए. आर. सिंधु ने सम्मेलन में शिरकत की।

सम्मेलन की शुरूआत जोशीले नारों के बीच एसोसिएशन की राज्य अध्यक्षा हबीब द्वारा झंडा फहराये जाने के साथ हुई। अखिल भारतीय महासचिव साथी हेमलता ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। राज्य महासचिव साथी पदमिनी द्वारा सम्मेलन में प्रस्ताव का मसौदा पेश किया इसमें उन्होंने पिछले सम्मेलन से इस सम्मेलन की सांगठनिक स्थिति और गतिविधियों का ब्यौरा पेश किया। प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्कर्स और हैल्पर्स को दिये जा रहे 100 रुपयों के अलावा केरल की सरकार 200 रुपये प्रति माह उन्हें उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा यह रकम 'पीपल्स प्लान' के साथ जुड़े कार्यकर्ताओं को भी मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने मांग की कि यह पैसा उन हैल्पर्स को दिया जाना चाहिये जिन्हें सरकारी आदेश के समय पर न आने के कारण यह नहीं मिल रहा है उन्होंने केरल की वाम-जनवादी मोर्चे की सरकार द्वारा मुहैया कराये जाने वाले त्यौहार बोनस और अन्य कल्याणकारी कदमों का भी जिक्र किया।

साथी पदमिनी ने जिला स्तर, प्रोजेक्ट कमेटी स्तर पर राज्य में कार्यरत तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स को संगठन के दायरे में लाने का आह्वान किया तथा संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने की अपील की।

सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने महासचिव द्वारा रखी गई रिपोर्ट पर बहस में हिस्सेदारी की और सर्वसम्मति से रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया।

सम्मेलन को बधाई देने वालों में सीटू व खेत मजदूर संगठन के अलावा दूसरे कई बिरादराना संगठन भी शामिल थे। अंत में सम्मेलन ने नई राज्य कमेटी का चुनाव किया तथा साथी हबीब को अध्यक्षा तथा साथी पद्मिनी को महासचिव चुना गया।

महाराष्ट्र राज्य रिपोर्ट

किरण मोधे

वर्ष 1998 में महाराष्ट्र सरकार ने 'राज्य महिला नीति' के तहत आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए कुछ अतिरिक्त कार्य की घोषणा की थी, ताकि ग्रामीण महिलाओं को लाभ हो और इसके लिए उन्हें अलग से पैसा दिये जाने की घोषणा भी हुई थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगभग 2000/- रुपया दिया जायेगा। राज्य के आंगनवाड़ी कर्मचारी बड़ी उम्मीद के साथ सरकारी आदेश के आने का इंतजार करते रहे हैं।

लेकिन 'सीटू' से संबंधित महाराष्ट्र आंगनवाडी कर्मचारी संगठन को पहले से ही सरकार की नीयत पर संदेह था और संगठन ने कर्मचारियों को आगाह करते हुए यह ऐलान किया था कि यदि सरकार अपने वादे से फिर जाती है तो उन्हें संघर्ष छेड़ने के लिए तैयार रहना चाहिये। संगठन की आशंका सही साबित हुई जब सरकार ने महीनों बीत जाने पर भी इस बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया। 10 जुलाई 98 को राज्यव्यापी अभियान छेड़ दिया गया और दूसरी यूनियनों को साथ लेकर नवम्बर में नागपुर में एक विशाल रैली आयोजित की गई। दबाव में आकर सरकार ने मजदूर प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक कमेटी बनायी जिसने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपीं। मगर भाजपा-शिवसेना की सरकार ने कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया। 16 मार्च को फिर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। जिसके बाद नये मुख्यमंत्री ने इस मामले पर गौर करने का वादा किया। लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया है।

ऐसा लगता है कि सरकार की ओर किया गया वादा सिर्फ एक चुनावी वादा था जिसे चुनाव बाद भुला दिया गया। अब चूंकि फिर चुनाव सामने है इसलिए इस चुनाव में यह जरूरी हो गया है कि भाजपा-शिव सेना गठबंधन को सबक सिखाया जाये।

हरियाणा यूनियन मीटिंग

–सरोज वासिष्ठ

हरियाणा के आंगनवाड़ी मजदूर व हेल्पर यूनियन के कार्यकर्ताओं के लिए दो दिवसीय राज्य स्तरीय शिक्षण शिविर का आयोजन रोहतक में किया गया। 5 से जून'99 को हुए इस शिक्षण शिविर में हरियाणा के 19 में से 9 जिनों के कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी री। प्रतिनिधियों के रहने व खाने का इन्तजाम सीटू राज्य समिति ने किया था। शिविर में जिन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई उनमें, देश के राजनैतिक व आर्थिक हालात, आंगनवाड़ी मजदूरों पर सरकार की नीतियों का प्रभाव, संगठन के सिद्धांत व महिलाओं से जुड़े मुद्दे आदि मुख्य विषय शामिल थे। शिविर में प्रोजेक्ट कमेटी के चुनाव व उनकी गतिविधियों में सुधार का फैसला लिया गया। जहाँ भी उपरोक्त कमेटियाँ मौजूद है। आंगनवाड़ी मजदूरों की मांगों पर प्रोजेक्ट स्तरीय धरना व 'रैली के आयोजन का फैसला लिया गया। तथा इनकी सफलता के लिए सशक्त अभियान चलाने पर जोर दिया गया। इस अभियान के तहत पर्चा बांटना तथा प्रोजेक्ट मिटिंग का आयोजन अनिवार्य है।

14 जून को एक राज्य स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ने समाज कल्याण व महिला विभाग की निदेशक से मिलकर मांग पत्र दिया। निदेशक ने बताया कि सुपरवाइजर के 100 प्रतिशत पद आंगनवाड़ी मजदूरों को ही दिये जायेंगे जिसके लिए नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया तथा इस बाबत सरकार को सिफारिश भेजने का भी आश्वासन दिया।

बीमा कर्मचारी नेता सरोज चौधरी नहीं रहे

17 जून की सुबह कलकत्ता में सरोज चौधरी का निधन हो गया। वह बीमा कर्मचारियों के आंदोलन के वयोवृद्ध नेता और सीटू के अखिल भारतीय सेक्रेटेरिएट के पूर्व सदस्य थे।

सरोज दा, देश के ट्रेड यूनियन परिदृश्य पर एक काबिल संगठनकर्ता और भारत में बीमा कर्मचारियों के जेहादी के रूप में उभर कर आये। वे तकरीबन दो दशक तक अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी एसोसिएशन के महासचिव रहे। बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिये चले अभियान और संघर्ष में उनके प्रयास अग्रगामी रहे। इसी संघर्ष के चलते पहले जीवन बीमा और बाद में साधारण बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ। साठ के जमाने में भारत में स्वचालन विरोधी संघर्ष में उनका योगदान अमूल्य था।

अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू) सरोज चौधरी के निधन पर शोक व्यक्त करती है और उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करती है।

संघर्ष की राह पर

पंजाब

त्रिपुरा

का. विमल रणदिवे–संयुक्त संघर्ष समिति रैली का नेतृत्व करते हुए

केरल

मध्य प्रदेश

सीटू के अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति के लिए विमल रणदिवे की ओर से 15, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, सम्पादित और प्रकाशित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रिएल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-95 से मुद्रित.